



VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)/GENERAL STUDIES (Paper-IV) (4513)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 62+2 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 62+2 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 01055139

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : ANANYA RANA

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

ENGLISH

तारीख
Date

27th JULY 2025

**सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)
GENERAL STUDIES (Paper IV)**

केंद्र
Centre

CHANDIGARH

Reh

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

	<p style="text-align: center;">महत्वपूर्ण अनुदेश</p> <p>उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।</p>	<p style="text-align: center;">Important Instructions</p> <p>Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.</p>
1	<p>(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें।</p> <p>(ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।</p>	<p>(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates.</p> <p>(b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet</p>
2	<p>अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।</p>	<p>Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.</p>
3	<p>परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।</p>	<p>Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.</p>
4	<p>उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।</p>	<p>Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.</p>
5	<p>उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।</p>	<p>Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.</p>
6	<p>प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।</p>	<p>Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.</p>
7	<p>प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।</p>	<p>Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.</p>
8	<p>यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।</p>	<p>If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.</p>

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
<p>परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)</p>	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1(a)			6 (a)		
1(b)			6 (b)		
2(a)			7		
2(b)			8		
3(a)			9		
3(b)			10		
3(c)			11		
4(a)			12		
4(b)					
5(a)					
5(b)					
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					



VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-IV)/GENERAL STUDIES (Paper-IV) (4513)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बारह प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions:

There are **TWELVE** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both, in **HINDI** and in **ENGLISH**.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. (a)

करुणा, दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानकर उसे महसूस करने तथा उस संबंध में कार्रवाई करने का साहसी विकल्प है, तब भी जब मौन रहना अधिक सुरक्षित हो और उदासीनता दिखाना अधिक सहज हो। भारत में सिविल सेवकों के लिए एक आवश्यक नैतिक मूल्य के रूप में करुणा के महत्व का परीक्षण कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Compassion is the courageous choice to feel another's suffering as one's own, and to act upon it, even when silence is safer and indifference is easier. Examine the significance of compassion as an essential ethical value for civil servants in India. Illustrate your answer with suitable examples. (Answer in 150 words)

Compassion refers to putting yourself into shoes of others and doing actions to find solutions to emancipate their sufferings (eg) Buddha's concept of Karuna

Compassion as courageous choice

① Not easy to speak up against authority

② Socialised to mind our business

③ Take extra effort to help others.

Significance of compassion as an essential ethical value for civil servants

① Promotes governance with a Knowledgeable head but Kind heart.

eg Keerthi Thalli, IAS went barefoot into floodwaters of Assam to address grievances

2. To build public trust and establish credibility of action.

eg Rajni Sekhri Sibbal, IAS pointed out corruption in JBT scam in Haryana.

3. To preserve the 'social contract' between people and the state.

eg Pradeep Kumar Jena, IAS as cyclone saviour in Odisha.

4. To enhance meaningful communication with the public.

eg Divya Derrajan, IAS learnt Gondi to interact with tribals.

5. To learn about true picture on ground

eg G. Sandeep, IAS, Chhatarpur went around inspecting on cycle.

Compassion is the lifeblood of relations in governance. There is nobility in compassion and beauty in empathy.

1. (b)

भारत में विवाह पारंपरिक संस्कारों से हटकर अधिक स्वायत्त संबंधों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो लिव-इन रिलेशनशिप की बढ़ती प्रवृत्ति और बढ़ती तलाक दरों से परिलक्षित होता है। इन परिवर्तनों के नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Marriages in India are transitioning from traditional sacramental unions to more autonomous relationships, reflected in live-in relationships and rising divorce rates. Discuss the ethical dimensions of these changes. (Answer in 150 words)

10

Marriage as an institution is evolving itself with the changing needs of the time. However, it is also giving rise to increasing confrontations and ethical dilemmas.

Transition of marriages in India

Sacramental unions → Autonomous relationships

- ① procreation purpose → companionship
- ② religious connotation → loyalty pledges
- ③ familial celebrations → individual pleasures
- ④ sacrosanct nature → no taboo on divorces
- ⑤ control on sexuality → pre-marital relationships

Ethical dimensions of these transitions

(1) Impact on intergenerational psychology
→ indifference towards familial responsibilities

(2) Breach of trust and loyalty
→ breaking values of truthfulness

(3) Promotion of immediate gratification
rather than collective well-being.

(4) Rise in deviant behaviour leading
to lack of accountability.

⊙ Shradha Walker murder case

(5) Promotion of broken window theory
with cheatings in relationships.

(6) Encourages aggressive actions and
breaking of relationships

The transitioning in marriage
institution need to evolve itself to
create a better world for all by checking
on its extravagant and consumeristic
behaviour

2. (a)

यद्यपि जवाबदेही के लिए प्रायः प्रलेखन आवश्यक होता है, लेकिन नौकरशाही प्रक्रियाओं और अत्यधिक कागजी कार्रवाई पर अधिक बल देने से अनजाने में उन आवाजों को दबाया जा सकता है जिन्हें लोक नीति, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, सशक्त करना चाहती है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ उपर्युक्त कथन का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

While accountability often necessitates documentation, an overemphasis on bureaucratic procedures and excessive paperwork can inadvertently silence the very voices that public policy intends to empower, particularly at the grassroots. Examine the above statement with suitable illustrations. (Answer in 150 words)

10

Accountability refers to responsibility along with answerability in all actions undertaken. It intends to create stronger credibility for work.

Accountability necessitates paperwork

① To have written record

② To prevent denial of responsibility

③ Preserve for future

④ To have objectivity in decision making

Excessive paperwork inadvertently harm the empowerment

① When complete focus is on means rather than ends.

① requirement of Aadhar from an old, flood affected lady asking for PDS.

② When compassion takes a backseat and emphasis is on ticking the boxes.

③ Want of documents in particular format only for compensation in Railway accident

④ It silences the already voiceless.

⑤ poor can't fight back the unnecessary demands

⑥ It sends wrong signals about intent of governance system

⑦ appears as harassing rather than facilitating.

⑧ Promotes mechanical approach in governance overpassing the needs on ground. ⑨ Special Intensive Revision in Bihar - allegations of genuine voters left out.

Documentation should complement accountability and become a vehicle to enhance transparency.

2. (b)

निष्पक्षता के सिद्धांत का कभी-कभी वंचित समुदायों के प्रति करुणा की आवश्यकता के साथ टकराव हो सकता है। भारत में सिविल सेवाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The principle of impartiality may conflict with the need for compassion towards marginalized communities. Discuss in the context of civil services in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हार्शिए में नहीं लिखना चाहिए - Candidate must not write on this margin

Principle of impartiality states that one should act with complete impartiality to status of person being served and would take decisions only on basis of objectivity.

Principle of impartiality may conflict with need for compassion

- (1) When situations are of scarcity.
eg) an earthquake affected area in need of food aid.
- (2) When action demanded is immediate
eg) rail accident in Balasore, Odisha
- (3) When legal provisions stand against social morality.

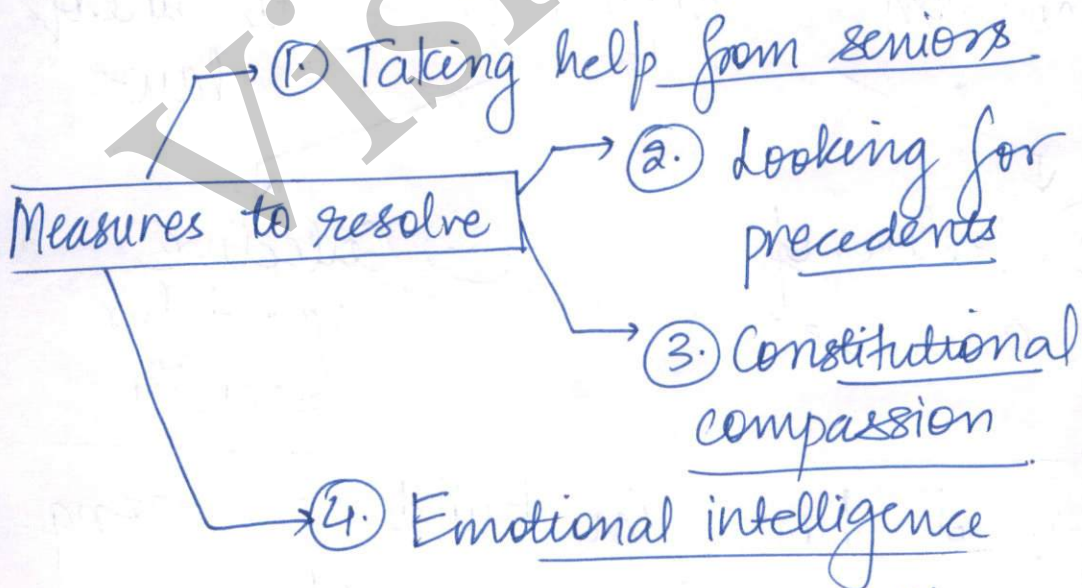
eg) restoration of right of Transgender to have freedom of ~~marriage~~ choosing partners.

4. When emotional overtones may lead to law and order situations.

eg) Minority community facing Wrath after Tablighi Jamaat case during COVID.

5. When demand is for harmonious construction

eg) people demanding death penalty for heinous crime.



Compassion and impartiality are faces of same coin. Need is to apply them with ethical conduct

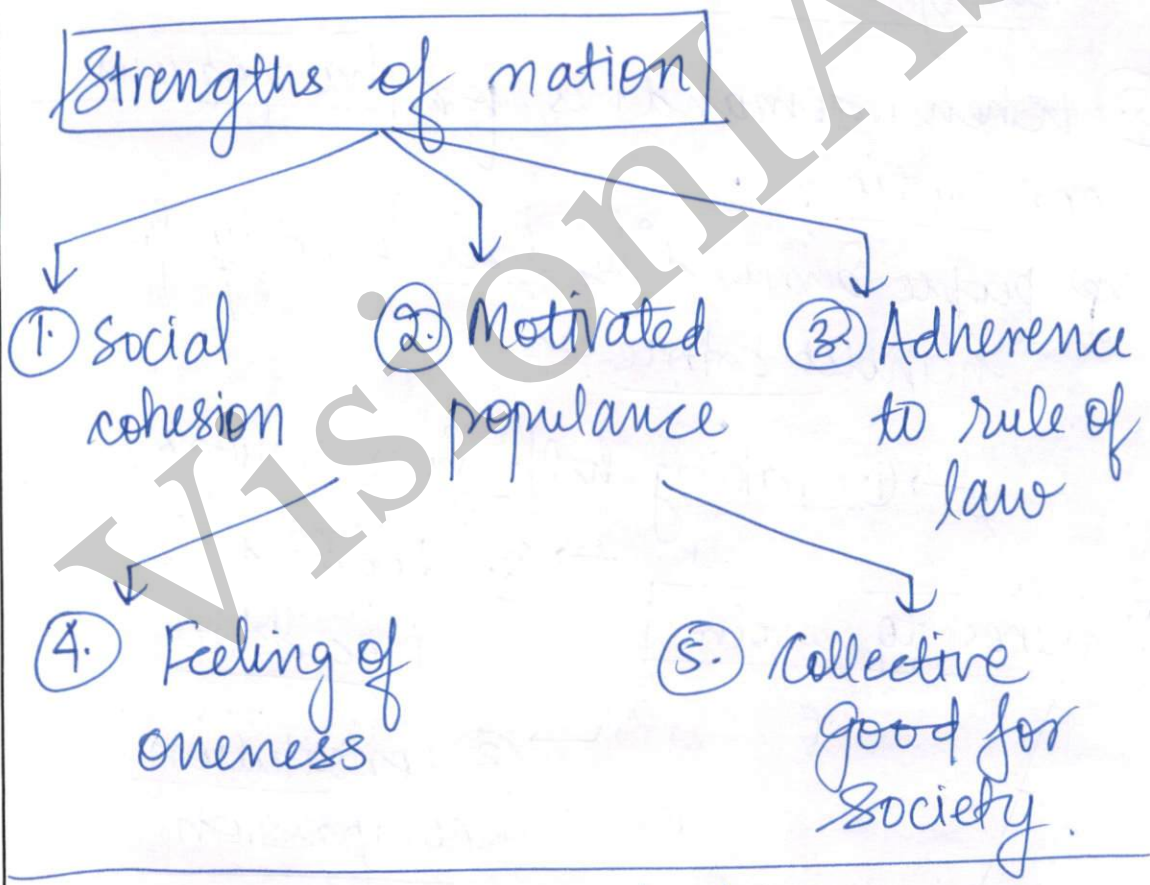
3. निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What do each of the following quotations mean to you?

(a) "किसी राष्ट्र की ताकत उसके घर की अखंडता से उत्पन्न होती है।" - कन्फ्यूशियस (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"The strength of a nation derives from the integrity of the home." - Confucius (Answer in 150 words) 10

This quote highlights the significance of principles of transparency, honesty and integrity in households culminating into building of a strong nation.



Role of home in building strong nation

1. Primary level of socialisation

where first lessons of universal love are taught.

② Learning by seeing - Children learn by emulating their elders.

③ Honesty in public life

④ Actions are replicated with other stakeholders. ⑤ Integrity at home will result in honesty at friendships.

⑥ Creates a chain reaction where every household displays ethical behaviour.

⑦ Committed to personal and national well being ⑧ Studying well, earning honestly, paying tax etc.

As Dr. Abdul Kalam remarked,
An empowered woman leads to
strengthened family, strong society
and a successful nation

3. (b)

"उसी नियम के अनुसार आचरण करें जिसके बारे में तत्क्षण आप सार्वभौमिक विधि बनाने का संकल्प कर सकें।"-
इमानुएल काण्ट (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

"Act only according to that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law."- Immanuel Kant (Answer in 150 words)

10

This quote presents the 'categorical imperative' of Kant where he focuses on universal morality of an act to be eligible as right conduct.

Universal morality of action should be the only way

① Focus on means rather than ends

② Corruption can never be justified.

③ Promotes simplistic style of action taking approach

④ lying can't be pursued.

⑤ Ensures no action is justified based on potential impact

④ Robin Hood like acts are never to be performed.

④ Oversees need to look at other perspective

④ situations demanding life and ~~death~~ ^{with} action

⑤ Deontological approach of actions is duty-based ethics.

→ ① National security concerns

④ A RAW agent may lie to a terrorist

→ ② To save lives

When this maxim faces challenge

④ A person's location may not be revealed to serial killer.

→ ③ To promote larger good

④ Euthanasia based on consent

→ ④ To help in life and death situations

④ abortion when life of mother at risk

Thus, this maxim has application based on context & circumstances

3. (c)

“हम न केवल उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो हम करते हैं, बल्कि उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं जो हम करने में विफल रहते हैं।” - मोलियर (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

“We are not only responsible for what we do, but also for what we fail to do” - Molière. (Answer in 150 words)

10

This quotation highlights the significant aspect of effect of inaction when needed in dire circumstances.

Responsible for not only what we do

① Direct attachment of accountability
eg) Slapping someone in rage

② Source can be detected
eg) Stealing of money

③ Clear relation between agent & receiver
eg) Asking bribe from commoner

④ Accountability and answerability can be fixed
eg) Accident cases.

Responsible also for what we fail
to do

① we fail as moral being

⊕ not speaking up against corruption
creates a chain

② Culture of apathy is carried
forward ⊕ not stopping road rage

③ Causes crises of conscience

⊕ not reporting case of
domestic violence against your
maid's husband.

④ Prevents chain of good action

and protects culprit.

⊕ strengthening of local gundas

Inaction in situations that
warrant strong reaction is equivalent
to being complacent in the
act

4. (a)

देशभक्ति नैतिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि राष्ट्रवाद प्रायः इसका दमन करता है। अत्यधिक दबाव वाली राष्ट्रीय घटनाओं के दौरान राजनीतिक अभिवृत्तियों के विकास के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। व्यक्ति ऐसी नैतिक अभिवृत्तियों को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय हित और नैतिक तर्क के बीच संतुलन स्थापित करें? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Patriotism encourages ethical questioning, while nationalism often suppresses it. Discuss this statement in light of the formation of political attitudes during high-pressure national events. How can individuals develop moral attitudes that balance national interest with ethical reasoning? (Answer in 150 words)

10

Patriotism refers to supporting the nation everytime and just when it deserves, while nationalism refers to unquestioned adherence to govt's actions.

Patriotism encourages ethical questioning while nationalism suppresses it

① Excessive nationalism clouds judgement of clarity.

② Support to Hitler during Nazi rule

③ It prevents objective decision making

④ Support of Pakistanis in terrorist attacks.

⑤ Genuine dissenters are labelled

anti-nationalists

- ⊙ Cases filed against WSJ journalists by US Prez on reports of Epstein case
- ④ Promotion of mass cancel culture for questions on appropriateness of action
- ⊙ Chinese actions against pro-democratic protests

→ ⑩ Critical thinking based on facts and figures

Measures needed to develop attitude balancing national interest with ethical reasoning

→ ② Promotion of ethical debates on national TV

→ ③ Support from political leaders about scientific temperament development

The need to differentiate between populism and ethical conduct is a sine qua non for effective functioning of democracies

4. (b)

चर्चा कीजिए कि निजी संगठनों में कर्मचारी कल्याण और निष्पक्षता को दक्षता एवं लाभप्रदता के साथ किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss how employee well-being and fairness can be balanced with efficiency and profitability in private organisations. (Answer in 150 words)

10

The work culture of an organisation which is based on ^{ethical} corporate governance tends to balance employee well-being and profitability of organisation.

Balancing of employee well-being and fairness & efficiency & profitability

① Adhering to pre-written Code of conduct ② Reward mechanism for employees

② Compassionate governance that takes into account needs of its stakeholders.

③ Tata announced salary to those killed during COVID-19.

③ Understanding principle of sustainability - which is based on long term well-being of all stakeholders.

ⓐ Google's policy of innovation with employee incentives.

④ Promotion of ethical working structure ⓐ payment of taxes, CSR etc.

⑤ Connecting with society to have a long term foresightedness.

ⓐ CSR activities of Tata.

To ensure employee well-being and profitability, leadership has to be moral in its working. It drives trust based institutions.

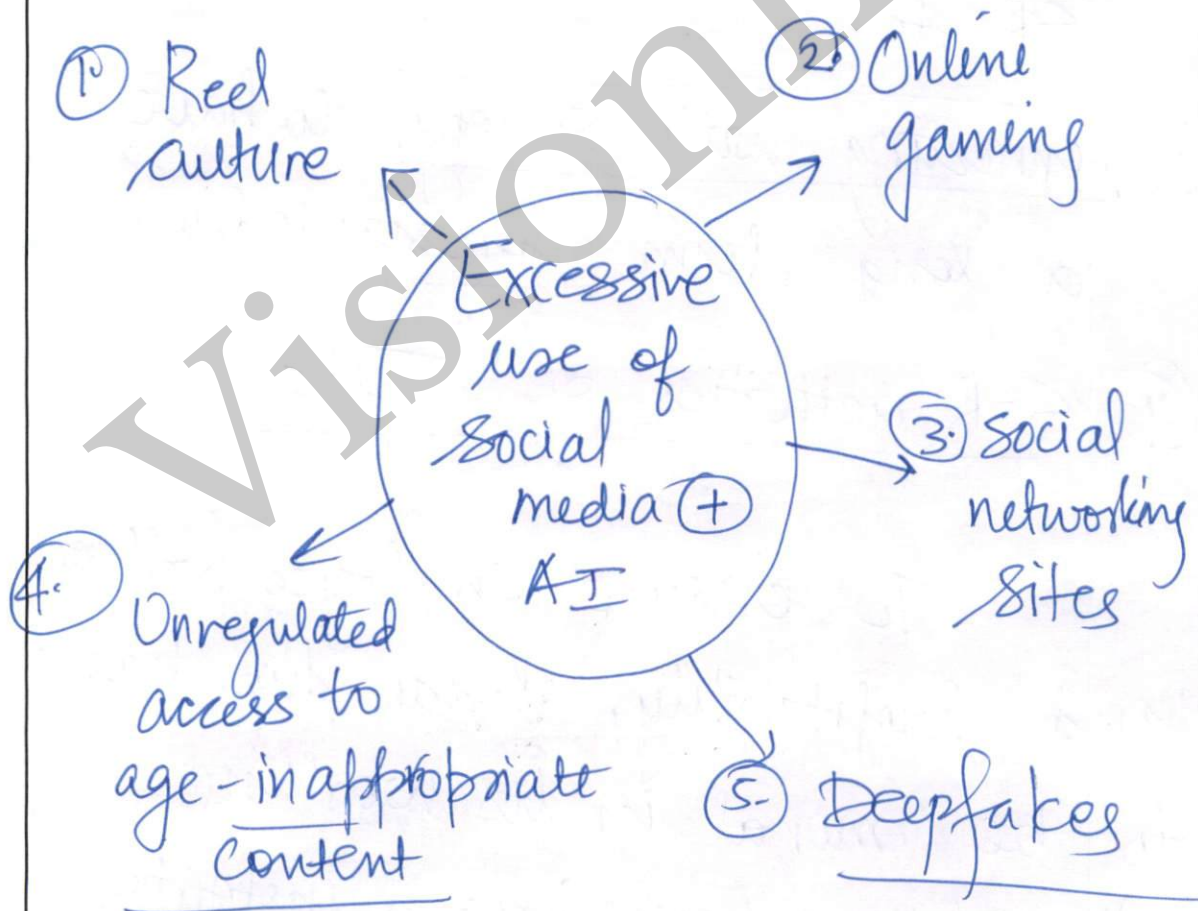
5. (a)

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सोशल मीडिया और उभरती हुई ए.आई. प्रौद्योगिकियों के अत्यधिक उपयोग से किशोरों में भावनात्मक नियमन और नैतिक संवेदनशीलता में कमी आ सकती है? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree that excessive use of social media and emerging AI technologies may lead to a decline in emotional regulation and moral sensitivity among adolescents? Justify your answer. (Answer in 150 words)

10

Emergence of Industry 4.0 having social media and AI is increasing screen time among adolescents sometimes leading to deviant behaviour -



Leading to decline in emotional regulation and moral sensitivity

① Increasing distance between 'real' and 'reel' life

② Mental health issues
(eg) insomnia
- aggressive stance

③ Sedentary lifestyle
↓
Cardiovascular, obesity

④ Deviant behaviour

- Bois locker group
- Bullibai, Sullideals.

Some +ves

① AI is need of future

② Better connection with far off friends

③ more knowledge gathering

Thus, technologies like social media and AI are not bad in themselves

It is how we use them that makes difference

5. (b)

भारत में छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के आलोक में, चर्चा कीजिए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ई.आई.) तनाव और भावनात्मक चुनौतियों के प्रबंधन में किस प्रकार सहायता कर सकती है। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In light of the increasing incidents of suicides among students in India, discuss how Emotional Intelligence (EI) can aid in managing stress and emotional challenges. (Answer in 150 words) 10

The rise in no. of suicides among students have brought to fore a significant issue of fall in resilience and lack of emotional management among them.

⑨ IIT Suicide cases

Role of EI in managing stress and emotional challenge

① Free flow of ideas among peers - understanding each others emotions

② Giving heed to instances of first deviation ⑨ social isolation

③ Adhering to path of sthit
pragya — holding oneself
unaffected by results
④ Kota students.

④ Promoting ethical conduct at
all times ④ preventing crises
of conscience.

⑤ Assuring mental support
when needed
④ peer help, self-awareness

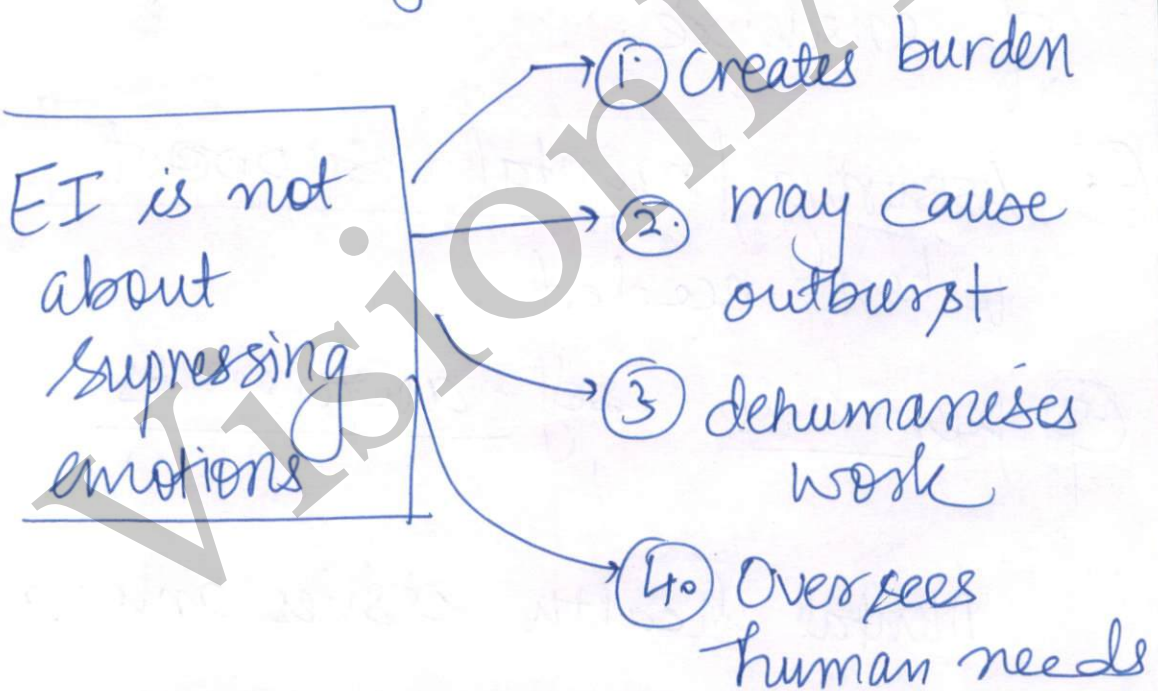
Mental health issues among
students need an empathetic
environment at all
stakeholder level —
professors, mates, families
etc

6. (a)

लोक सेवा में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि समानुभूति और शक्ति के साथ दूसरों से जुड़ने, तनाव या टकराव शांत करने तथा उनका उत्थान करने के इसके उद्देश्य में निपुणता प्राप्त करना है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In public service, emotional intelligence is not about suppressing emotion, but mastering its purpose — to connect, to de-escalate, and to uplift others with empathy and strength. Do you agree with this view? Discuss. (Answer in 150 words) 10

Emotional intelligence refers to understanding one's own and others' emotions to take righteous decisions.



EI - mastering its purpose

① To connect with peers, family members etc.

whenever need arises.

① for students.

② To de-escalate from a potentially threatening situation -

④ suicidal thoughts.

③ To uplift others by understandi
ng their mental needs

④ to motivate, to give
shoulder in need.

④ To promote compassion
and well being of those
suffering from accidents of life
- COVID

④ EI leads to soj. success
in workplace?
- Daniel Goleman

6. (b)

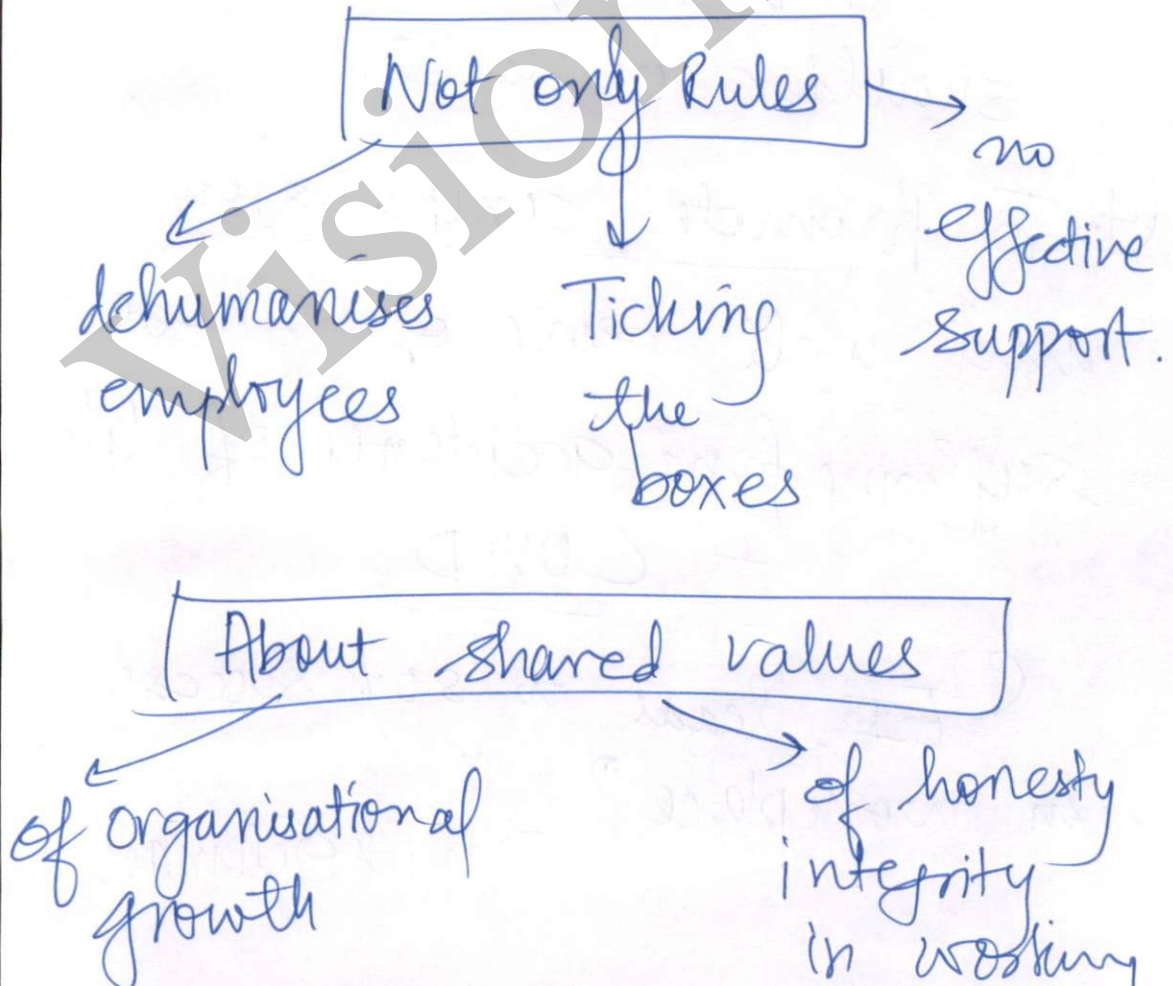
एक कुशल कार्य संस्कृति का निर्माण केवल नियमों पर नहीं, बल्कि साझा मूल्यों पर आधारित होता है। इस संदर्भ में, किसी संगठन के भीतर कार्य संस्कृति को परिवर्तित करने में नेतृत्व और टीम के पारस्परिक व्यवहार के तरीके की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An efficient work culture is built not only on rules, but on shared values. In this context, evaluate the role of leadership and team dynamics in transforming work culture within an organization. (Answer in 150 words)

उम्मीदवारों को इस हिसाब में नहीं लिखना चाहिए -
Candidate must not write on this margin

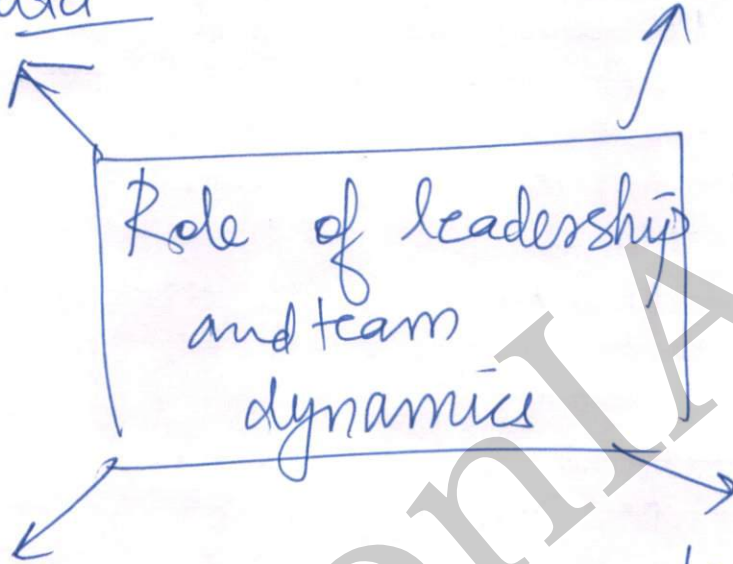
10

Work culture refers to processes and procedures at the organisation of work that emphasis well being of all stakeholders.



Democratic
leadership
@ Tata

Focus on
productivity
and well being



Critical
discussion
on improvements

Help
during
need
@ accidents
of life

Organisations like Tata
work on employee well-being
This ensure

7.

आप एक राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में, सरकार ने कई नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं लागू की हैं, जिनके माध्यम से बड़ी मात्रा में निवासियों से व्यक्तिगत डेटा एकत्र किया जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के अनुसार, ऐसे डेटा को केवल स्पष्ट और सूचित सहमति के साथ ही संसाधित किया जाना चाहिए और यदि व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले लेता है, तो डेटा का संसाधन तुरंत रोकना अनिवार्य है।

एक आंतरिक ऑडिट के दौरान, आपको पता चलता है कि विभाग कई नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को उनके द्वारा अपनी सहमति औपचारिक रूप से वापस लेने के बावजूद संसाधित और विश्लेषित कर रहा है। इस डेटा का उपयोग नीति विश्लेषण और सेवा सुधार जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो डेटा एकत्र करते समय स्पष्ट रूप से बताए नहीं गए थे। जब आप इस मुद्दे को विभाग प्रमुख के संज्ञान में लाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि डेटा संसाधन को रोकने से चल रही डिजिटल पहलें बाधित हो सकती हैं और राज्य स्तर के प्रदर्शन संकेतक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको यह भी पता चलता है कि सहमति वापसी की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है और अधिकांश नागरिकों को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है।

आपको यह भी पता चलता है कि एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत डेटा के बिना सहमति के उपयोग के विरुद्ध डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है, जिससे विभाग के विरुद्ध सार्वजनिक जांच और विधिक कार्रवाई हो सकती है।

- इस प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान करते हुए उन पर चर्चा कीजिए।
- यदि इस मुद्दे का पारदर्शी तरीके से समाधान नहीं किया गया तो विभाग के लिए संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?
- आप कुशल लोक सेवा वितरण की आवश्यकता और नागरिकों के डेटा अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are posted as the Joint Secretary in the Department of Information Technology of a state. The government recently implemented several citizen-centric digital services, collecting large volumes of personal data from residents. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, requires that such data be processed only with explicit and informed consent, and mandates that processing must cease immediately upon withdrawal of consent.

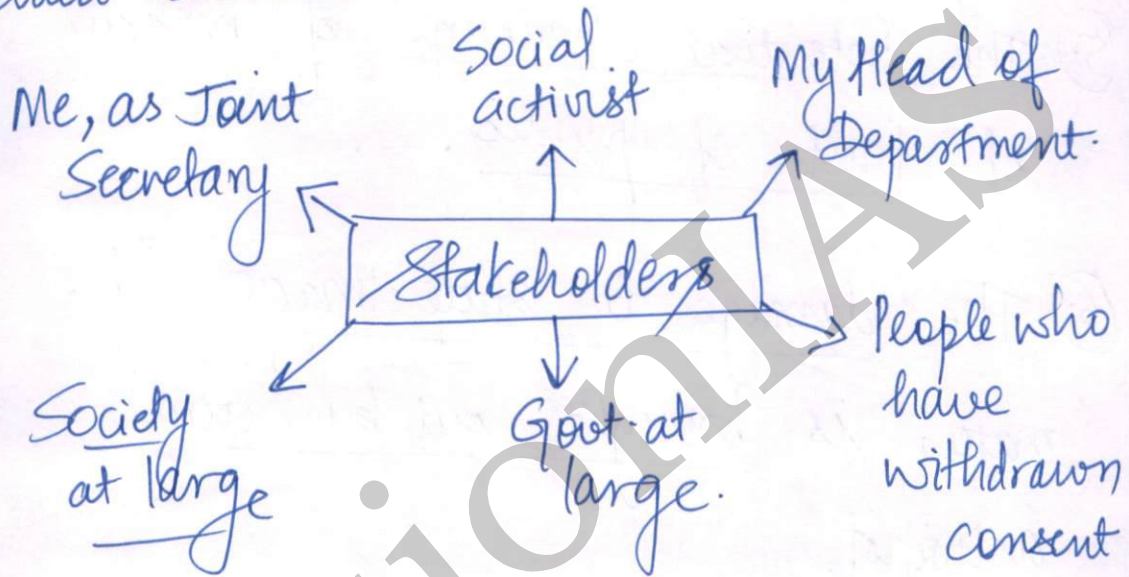
During an internal audit, you discover that the department continues to process and analyze personal data of several citizens even after they have formally withdrawn their consent. This data is being used for policy analytics and service improvement, purposes not explicitly disclosed at the time of data collection. When you bring this to the attention of your department head, you are informed that halting the processing will disrupt ongoing digital initiatives and may affect state-level performance metrics. Moreover, you find that the consent withdrawal process is cumbersome, and many citizens are unaware of their rights under the DPDP Act.

You also learn that a prominent social activist is planning to file a complaint with the Data Protection Board against involuntary use of personal data, which could attract public scrutiny and legal action against the department.

- Identify and discuss the ethical issues involved in this case.
- What are the potential consequences for the department if the issue is not addressed transparently?
- How would you balance the need for efficient public service delivery with the obligation to protect citizens' data rights? (Answer in 250 words)

20

a This case study highlights the ethical dilemma between right to privacy of individuals v/s obligation to enhance public welfare involved in data collection.



(a) The ethical issues involved in the case are:

- ① The legal wrong being done by department in processing data for purpose not given explicit consent.
- ② The issue of persistente use of data even after consent withdrawal.

(3) Greyzone area where people are not even aware about provisions under DPDP Act.

(4) The lack of accountability of head of my department - calling to overlook matter

(5) The potential challenge of breach of trust of public.

(6) The damage to state's image if matter is brought out by social activist

(7) The misuse of data furthering the 'Broken window theory'

(b)

Potential consequences for the department if issue is not addressed transparently

(1) Immediate loss of public trust in governance

(2) Protector of law would become

violators themselves.

(3) Threat of issue being internationalised

(4) Reputational damage to state govt. and the department.

(5) Filing of case against responsible authorities, including me under provisions of DPDP Act.

(6) Consent withdrawal may lead to disruption in data analytics w.r.t. policy formulations.

(c)

The situation demands immediate action based on transparency and objectivity. My course of action would be:

(I) To protect citizen's data rights

① Immediate publication of order to respective stakeholders to ask for consent of public for said purpose

- ② Raising awareness about rights of individuals under DPDP Act so that those not aware may take action.
- ③ Simultaneously, pausing the data use for work not specified.
- ④ Consulting with social activist and using my power of persuasion to make him not file the case till authorities take final decision.

(II) For efficient public service delivery

- ① Public service delivery demands complete transparency & integrity.
- ② Data analytics should only be done in accordance with the Act
- ③ When consent is resumed, start data analysis for the said purpose
- ④ Clear guidelines for future.

These actions promote ethical conduct on my part & display my 'courage of conviction' to act in public welfare

8.

आप एक IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में एक पहाड़ी राज्य में लोक निर्माण विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में, एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो अभियंताओं से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। एक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना के निरीक्षण के दौरान, मंत्री को कथित रूप से एक वीडियो में सार्वजनिक रूप से अभियंताओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया। यह वीडियो वहां से गुजर रहे लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तथा टेलीविजन चैनलों द्वारा भी इसे व्यापक रूप से कवर किया गया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में आक्रोश और समर्थन दोनों देखने को मिला। बाद में मंत्री ने अपने कृत्य का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी भ्रष्ट हैं, स्थानीय शिकायतों के प्रति अनुत्तरदायी हैं और परियोजना में अत्यधिक विलंब के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्री द्वारा यह भी कहा गया कि उसका व्यवहार जनता की निराशा और दूरस्थ क्षेत्र में समय पर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता से प्रेरित था।

हालांकि, अभियंताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर यह दावा किया है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने मंत्री से जुड़े स्थानीय ठेकेदारों को ठेका देने के लिए डाले जा रहे राजनीतिक दबाव का विरोध किया था। स्थिति के अधिक गंभीर होने पर, NHAI अभियंताओं के एक संघ ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई और अधिकारी की गरिमा की रक्षा की मांग करते हुए हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके कारण कई महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं ठप हो गई हैं, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क, मानसून पूर्व मरम्मत कार्य और सामरिक सीमा सड़कें शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने आपको तथ्यान्वेषण रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच, मंत्री का कार्यालय आप पर अनौपचारिक रूप से घटना को कम महत्वपूर्ण दिखाने का दबाव बना रहा है। मीडिया दो भागों में बंटा हुआ है — कुछ मंत्री को भ्रष्टाचार के विरुद्ध योद्धा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे प्रशासनिक आचरण और विधि के शासन का गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं। विभिन्न विभागों के सिविल सेवकों ने व्यक्तिगत सुरक्षा, गरिमा और राजनीतिक हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है, वहीं अवरुद्ध अवसंरचना कार्यों के कारण नागरिकों में भी असंतोष बढ़ रहा है।

- इस प्रकरण में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं? हितधारकों और उनके परस्पर विरोधी हितों की पहचान कीजिए।
- लोक निर्माण विभाग के सचिव के रूप में, आप उपर्युक्त स्थिति में क्या कार्रवाई करेंगे?
- ऐसी घटनाएं सिविल सेवकों के मनोबल और शासन में जनता के विश्वास को कैसे प्रभावित करती हैं? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are an IAS officer, currently serving as the Secretary of the Public Works Department in a hill state. Recently, a disturbing incident has come to light involving a senior Cabinet Minister and two engineers of the National Highways Authority of India (NHAI). During an inspection of a critical highway project, the Minister was allegedly seen on video physically assaulting and verbally abusing the engineers in full public view. The video, recorded by bystanders, went viral on social media and was widely covered by television channels, sparking both outrage and support from different sections of society. The Minister later defended his actions, alleging that the officials were corrupt, unresponsive to local grievances, and responsible for inordinate delays in the project. He insisted that his actions were driven by public frustration and the urgency of delivering infrastructure to a remote region.

However, the engineers have filed a police complaint and written to their superiors, claiming they were targeted for resisting political pressure to award contracts to specific local contractors linked to the Minister. As the situation escalated, a union of NHAI engineers declared a strike,

demanding action against the Minister and protection of officer dignity. This has brought several critical infrastructure projects to a standstill, including road connectivity to tribal areas, pre-monsoon repair works, and strategic border roads.

You have been directed by the Chief Secretary to prepare a fact-finding report, while also ensuring smooth coordination between state and central agencies. Meanwhile, the Minister's office is informally pressuring you to downplay the incident. The media is sharply divided — some portraying the Minister as a crusader against corruption, others condemning the act as a serious breach of administrative ethics and rule of law. Civil servants across departments have expressed concern about personal safety, dignity, and increasing political interference, while citizens are now growing restless due to halted infrastructure works.

- (a) What are the key ethical issues involved in this situation? Identify the stakeholders and their conflicting interests.
- (b) As the Secretary of the PWD, what actions will you take in above situation?
- (c) How do such incidents affect the morale of civil servants and public trust in governance?
(Answer in 250 words)

20

This incident points a similarity to a case in Himachal Pradesh where two engineers from NHAI were allegedly assaulted in private. The solution demands strict adherence to legal mandate and following the path of righteousness.

(a) Key ethical issues involved in this situation :

- (1) The violation of law on 'disrupting a public servant from disposing his/her duty'
- (2) Use of physical force against a public servant.

- (3) The unethical pressure being put on my office to downplay the incident.
- (4) The urgency to fulfill public mandate of infrastructural projects.
- (5) The genuine concerns of civil servants regarding their safety at workplace.
- (6) The biased nature of media to come at conclusion without formal inquiry.
— Post Truth journalism.

Stakeholders	Conflicting interests
① People of the state	Want infrastructural project completion
② Minister	Want public sympathy & gain of vote bank
③ The NHAI engineers	Strict punishment for violators, ensurance of safety at workplace
④ Me, as Secretary of PWD	Completion of projects while ensuring no such future incidents happen & accused/ culprits are <u>punished</u> .

(b) My course of action in this situation

① In-depth inquiry orders into the incident

② Protection of officers involved in inquiry from undue pressure from any side

③ Addressing the union of NHA engineers and passifying them about the free and fair inquiry being conducted. Negotiate with them to rejoin work

④ Not budging to the informal pressures from Minister's office

⑤ Submitting complete and transparent fact-finding report to Chief Secretary.

⑥ Addressing people and assuring them of re-start of projects.

⑦ Projecting myself as an officer of integrity without pre-assessment ~~in~~ before report submission

(C) Effect of such incidents:

On morale of civil
Servants

On public trust in
governance

- | | |
|---|---|
| <p>① It <u>prevents</u> them from fulfilling their <u>duties</u> without <u>fear</u> or <u>favour</u>.</p> <p>② It creates a psychological crises where they are worried about their safety at all times.</p> <p>③ Reduces efficiency at workplace.</p> <p>④ Does reputational damage.</p> <p>⑤ Prevents other officers from taking righteous path.</p> | <p>① Biased media news creates suspicion in their minds.</p> <p>② Paints entire bureaucracy as being corrupt.</p> <p>③ Right to <u>know</u> correct information is <u>violated</u>.</p> <p>④ Promote <u>distance</u> between citizens and governance mechanism.</p> |
|---|---|

The safety and security of officials at workplace is a sine-qua non for effective public service delivery.

9.

आप भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल के वर्षों में, लोक सेवकों, विशेष रूप से IAS, IPS और IRS से संबंधित ऐसे युवा अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज बना रहे। इन प्लेटफार्मों पर, वे नियमित रूप से अपने आधिकारिक कार्यों — नवाचारी परियोजनाओं, जनसंपर्क पहलों, निरीक्षण यात्राओं और कभी-कभी दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों - से संबंधित वीडियो भी पोस्ट करते हैं।

इन वीडियो पर प्रायः व्यापक रूप से जनता द्वारा ध्यान केंद्रित दिया जाता है और कई दर्शक यह कहते हुए इसकी सराहना करते हैं कि ऐसी सामग्री पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, अभ्यर्थियों को प्रेरित करती है और नौकरशाही को मानवीय बनाती है। हालांकि, विभिन्न वर्गों से कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। वरिष्ठ अधिकारी तर्क देते हैं कि ऐसी सामग्री व्यक्तिगत ब्रांडिंग और लोक सेवा के बीच की सीमाओं को धुंधला कर सकती है, जबकि कुछ नागरिक और मीडिया विश्लेषक ऐसे उदाहरणों की ओर संकेत करते हैं, जहां वीडियो में बिना सहमति के सुभेद्य लाभार्थियों को दिखाया जाता है, आधिकारिक परिसरों का दुरुपयोग किया जाता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो सार्वजनिक उत्तरदायित्व की तुलना में व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने हेतु बनाए गए हैं। एक प्रकरण में, एक जिलाधिकारी को एक विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को कैमरे पर डांटते हुए देखा गया — यह वीडियो बाद में उनके व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया, जो मोनेटाइज भी है। कुछ लोगों ने अधिकारी द्वारा अपनाए गए सख्त रवैये की सराहना की, जबकि अन्य ने शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से डांटने और सेवा की गरिमा का उल्लंघन करने की आलोचना की। एक अन्य मामले में, एक पुलिस अधिकारी को बाढ़ बचाव अभियान का निर्देशन करते हुए देखा गया, जहां उसके कर्मचारी ड्रोन कैमरे में माध्यम से इसे फिल्मा रहे थे, जिसे बाद में सोशल मीडिया के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो के रूप में संपादित किया गया। आपको लोकहित, संस्थागत सत्यनिष्ठा और संचार के बदलते तरीकों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु अनुशंसाओं सहित एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

- लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के कृत्यों में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।
- क्या ऐसी प्रथाएं जागरूकता और प्रेरणा को प्रोत्साहन देती हैं या क्या ये अनामिता, तटस्थता और सामूहिक सेवा भावना के मूल्यों से समझौता करती हैं? अपना मत दीजिए।
- सचिव के रूप में, लोक सेवकों की उत्तरदायी डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आप कौन-से मार्गदर्शक सिद्धांत और नीतिगत अनुशंसाएं सुझाएंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

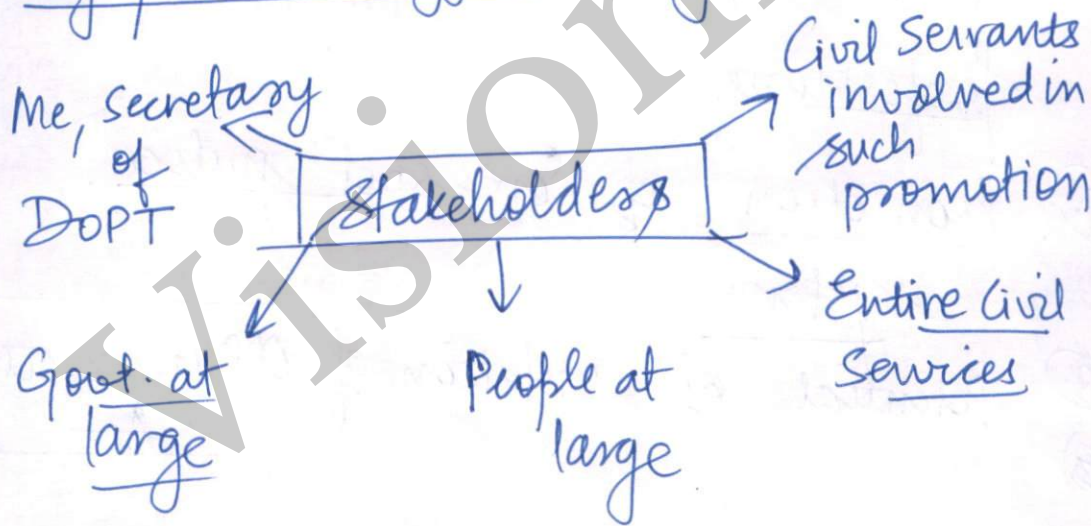
You are the Secretary in the Department of Personnel and Training (DoPT), Government of India. In recent years, an increasing number of civil servants, particularly younger officers from the IAS, IPS, and IRS, have begun maintaining personal YouTube channels and social media pages. On these platforms, they regularly post videos related to their official work — showcasing innovative projects, public outreach initiatives, inspection drives, and sometimes even day-to-day administrative duties.

These videos often receive widespread public attention, and many viewers express admiration, saying such content enhances transparency, motivates aspirants, and humanizes the bureaucracy. However, concerns have also emerged from various quarters. Senior officers argue that such content may blur the boundaries between personal branding and public service, while some citizens and media commentators point to instances where videos feature vulnerable beneficiaries without consent, raise concerns about misuse of official premises, or seem designed more for personal popularity than public accountability.

In one case, a district magistrate was seen filming a surprise school inspection in which teachers were scolded on camera — the video was later posted to his personal YouTube channel that is also monetized. While some praised the officer's strictness, others criticized the public shaming of teachers and the breach of service dignity. In another case, a police officer was seen directing a flood rescue operation while his staff filmed drone footage, later edited into a motivational video for social media. You have been asked to prepare a report with recommendations to balance public interest, institutional integrity, and evolving modes of communication.

- Identify the ethical issues involved in civil servants publicly showcasing their official work on social media.
- Do such practices promote awareness and motivation, or do they compromise the values of anonymity, neutrality, and collective service ethos? Give your opinion.
- As the Secretary, what guiding principles and policy recommendations would you suggest to ensure responsible digital engagement by civil servants? (Answer in 250 words) 20

This situation festains to excessive usage of social media platforms to convey information, often disguising self-praise as official obligations.



(a) Ethical issues involved in this situation:

① Violation of principles of Civil Services — anonymity [to work as 4th Lion of the Ashoka Stambha]

- ② Official duty being popularised as something extra-ordinary
- ③ Projection of officials as demi-gods
- ④ Promotion of idea of Civil Servants being the only saviour.
- ⑤ Public image/disreputation of those involved in videos - teachers
- ⑥ Violation of service dignity of all professions
- ⑦ Promotion of 'on-spot' justice system.
- ⑧ Potential of violation of Official Secrets Act

(b) Significance of such videos/content

- ① Raise public awareness about works of a civil servant.
- ② Make public aware about their rights

- ③ Ensures transparency in inspections
- with recorded account.
- ④ Can act as future evidence to defend
any case of assault on officer.

As means of promotion - when excessive
use.

- ① Present Civil Servants as heroes
- ② Promotes by-passing of legal process
to approach them for all works
- ③ Blurs the fine line between
public information and self-promotion
- ④ Creates a chain of such acts
among 'new entrants'

(c) Guiding principles and policy
recommendations for responsible use.

- ① Separating the private account
from public ones - with explicit
mention

- उम्मीदवारों को इस हिसाब से नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin
- ② Limiting use of video and content being posted on special inspections.
 - ③ Due regard for privacy of individuals being shot.
 - ④ Complete pausing of use of these channels as monetizing tools - violation of Civil Services Rules.
 - ⑤ Promotion of ideals of 'Shishtachaar' as taught at LB SNAA.
 - ⑥ Decreasing culture of consumerism among civil servants by guiding them about conduct of senior officials

'Anonymity, Austerity and ability' are the three great virtues of civil servants. They must be strictly adhered to for ensuring public responsibility and efficient public service delivery

आप नेशनल बायोएथिक्स कमीशन के निदेशक हैं, जो एक राष्ट्रव्यापी जीन अनुक्रमण कार्यक्रम की नैतिक व्यवहार्यता और निगरानी का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। "जीन फ्यूचर" नामक इस परियोजना का उद्देश्य प्रत्येक नवजात शिशु के डी.एन.ए का अनुक्रमण करना और उसे एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रहीत करना है। इसका उद्देश्य जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही गंभीर बीमारियों के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्तियों की पहचान करना है, ताकि निवारक उपचार और वैयक्तिकृत चिकित्सा संभव हो सके। इस कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण में पहले ही 1,00,000 से ज्यादा शिशुओं को नामांकित किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि यह जन स्वास्थ्य उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

यद्यपि, नवजात शिशुओं के आनुवंशिक डेटा का संग्रह गंभीर नैतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है, विशेष रूप से सूचित सहमति के संबंध में, जो संभवतः दीर्घकालिक जोखिमों के बारे में माता-पिता की समझ को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। एक बार एकत्रित हो जाने के बाद, इस संवेदनशील डेटा का दुरुपयोग निगरानी, बीमा भेदभाव या तृतीय पक्षों द्वारा व्यावसायिक विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। डेटा के स्वामित्व को लेकर अनिश्चितता—कि यह राज्य का है, माता-पिता का है, या उस बच्चे का है जब वह बयस्क होगा—इस मुद्दे को और जटिल बना देती है। निजी तकनीकी और दवा कंपनियों की संलिप्तता से वाणिज्यिक शोषण की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, विशेष रूप से इस प्रकार के स्पष्ट तंत्र के अभाव में, जिसके तहत बयस्क होने पर व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले सकता है या अपनी आनुवंशिक जानकारी को हटा सकता है।

- आपके विचार में जीन फ्यूचर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन-से नैतिक मुद्दे शामिल हैं?
- इस प्रकरण में विभिन्न हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों की पहचान कीजिए।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आप किन मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांतों की अनुशंसा करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are the Director of the National Bioethics Commission who is responsible for assessing the ethical feasibility and oversight of a nationwide gene sequencing program. The project named GeneFuture, aims to sequence the DNA of every newborn child and store it in a centralized national database. The objective is to identify genetic predispositions to serious diseases early in life, allowing for preventive treatment and personalized medicine. Over 100,000 babies have already been enrolled in the pilot phase of the program. The government claims that this move is a landmark step in public health advancement.

However, collection of newborn genetic data raises significant ethical concerns, particularly around informed consent, which may not fully capture parents' understanding of the long-term risks involved. Once gathered, this sensitive data could be misused for purposes such as surveillance, insurance discrimination, or commercial marketing by third parties. Uncertainty over data ownership—whether it lies with the state, parents, or the individual as they mature—further complicates the issue. The involvement of private tech and pharmaceutical companies heightens fears of commercial exploitation, especially in the absence of clear mechanisms for individuals to withdraw consent or delete their genetic information upon reaching adulthood.

- What are the ethical issues you perceive in the implementation of the GeneFuture program?
- Identify the conflicting interests of different stakeholders in this case.
- What guiding ethical principles would you recommend for implementation of this project?
(Answer in 250 words)

This case presents an ethical dilemma about duty to perform act in public interest v/s protection of individual rights.

(a) Ethical issues involved in the case:

① The issue of grey zone where usage of data in future is not clear.

② Clear, informed and coercionless consent from parents required.

③ Involvement of private sector heightens the risk of misuse of data.

④ The treatment of data few decades down the

lane is also not clearly defined.

(5) Issues wrt data ownership - to decide data fiduciary and data principle under DPDP Act, 2023.

(6) My duty as Director to ensure Future Gene Project is able to reach its ~~attains~~ intended goal

(7) My concerns about responsible use of data of new borns

(8) Entire image of state at stake.

(b) Stakeholders and their conflicting Interests

<u>Stakeholders</u>	<u>Conflicting interests</u>
(1) State govt.	want analysis of data to have better healthcare 49

(2) Parents of
new borns

want data usage
in responsible
manner.

(3) New borns

not even aware
about such an
issue

(4) Private tech
and pharmaceutical
companies

Profit motive,
may potentially
have interest to
monetise data
in future

(5) Third parties

Insurance companies
may exploit
data to sell
their policies &
increase premiums
according to
threat perception

(c) Guiding ethical principles that I would recommend :

- ① Clear guidelines should be laid down about use of data.
- ② Then only, parental consent must be sought with provision of withdrawing consent once child becomes major.
- ③ Timelines about storage of data.
- ④ Verification of private players and clear mention in contract about usage of data by them.
- ⑤ Strict penalties on leakage of data.
- ⑥ No selling of data to third parties.

Business without morality is a sin and public servants here are guardians of ethical use of data of public. They must show extreme caution and spirit of justice at all times.

आप एक समर्पित जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) हैं और आप साक्ष्य-आधारित जन स्वास्थ्य पद्धतियों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता रखते हैं। हाल ही में, आपको भारत के एक दूरस्थ जिले में नियुक्त किया गया है। आपका तात्कालिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य एक प्रमुख जिला-व्यापी खसरा-रूबेला (MR) टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करना है, जिसका उद्देश्य 9 महीने से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 100% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है। इस अभियान की सफलता हजारों बच्चों के सामूहिक स्वास्थ्य और जिले के समग्र स्वास्थ्य संकेतकों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब आने वाला मानसून का मौसम स्वास्थ्य संबंधी अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है।

हालांकि, आपके जिले के सबसे बड़े और सबसे पारंपरिक गाँवों में से एक में, आपको अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। एक प्रतिष्ठित स्थानीय आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित ग्रामीणों का दृढ़ विश्वास है कि टीकाकरण दुष्ट आत्माओं का आक्रमण है एवं बाहरी ताकतों द्वारा उनकी आबादी को नियंत्रित करने का एक प्रयास है और यह उनके बच्चों में बांझपन का कारण बनेगा। वे ज़ोर देकर कहते हैं कि उनके पारंपरिक औषधीय उपचार और अनुष्ठानिक आशीर्वाद ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह आध्यात्मिक गुरु, जो वास्तव में नेकनीयत किंतु अडिग व्यक्ति है, वास्तविक रूप से मानते हैं कि ये टीके हानिकारक होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अनुयायियों को इसका विरोध करने की सलाह दी है। इसके लिए वह टीकाकरण की कुछ कथित 'विफलताओं' और प्राचीन भविष्यवाणियों का उदाहरण देता है। पारंपरिक जीवन-शैली का पालन करने वाले समुदाय के लिए उसके निर्देश या सलाह सर्वोपरि हैं। इसके कारण व्यापक जागरूकता अभियानों के बावजूद, गाँव में टीकाकरण शिविरों का लगभग पूर्ण बहिष्कार किया गया है। आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, जिनमें से कुछ स्थानीय हैं और जिन्हें सामाजिक बहिष्कार या यहाँ तक कि शारीरिक हमले का भय है, तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अत्यधिक दबाव बना रहा है और चेतावनी दे रहा है कि यदि कोई ज़िला इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही, विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि बल प्रयोग किसी भी परिस्थिति में न किया जाए क्योंकि इससे जन असंतोष उत्पन्न हो सकता है। साथ ही, विभाग ने 'सहमति-आधारित' लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया है। इसी बीच, एक बड़ा वार्षिक मेला आयोजित होने वाला है जिसमें कई गाँवों और क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। यदि यह गाँव बिना टीकाकरण के रह गया, तो इससे खसरा-रूबेला (MR) के प्रकोप के प्रसार का तात्कालिक और गंभीर खतरा है, जो पूरे जिले और संभवतः उससे आगे तक फैल सकता है।

- उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
- इस विरोध को शांत करने के लिए आपके पास तत्काल क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- अंधविश्वास के व्यापक प्रभाव को दूर करने और संधारणीय लोक स्वास्थ्य परिणामों हेतु वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आप कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियां और प्रणालीगत सुधारों का सुझाव देंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are a dedicated District Health Officer (DHO) with a strong commitment to evidence-based public health practices, recently assigned to a remote district in India. Your immediate and most critical task is to lead a crucial district-wide Measles-Rubella (MR) vaccination drive, aimed at achieving 100% immunization coverage among children aged 9 months to 15 years. The success of this drive is vital for the collective health of thousands of children and for the district's overall health indicators, especially with the impending monsoon season posing additional health challenges.

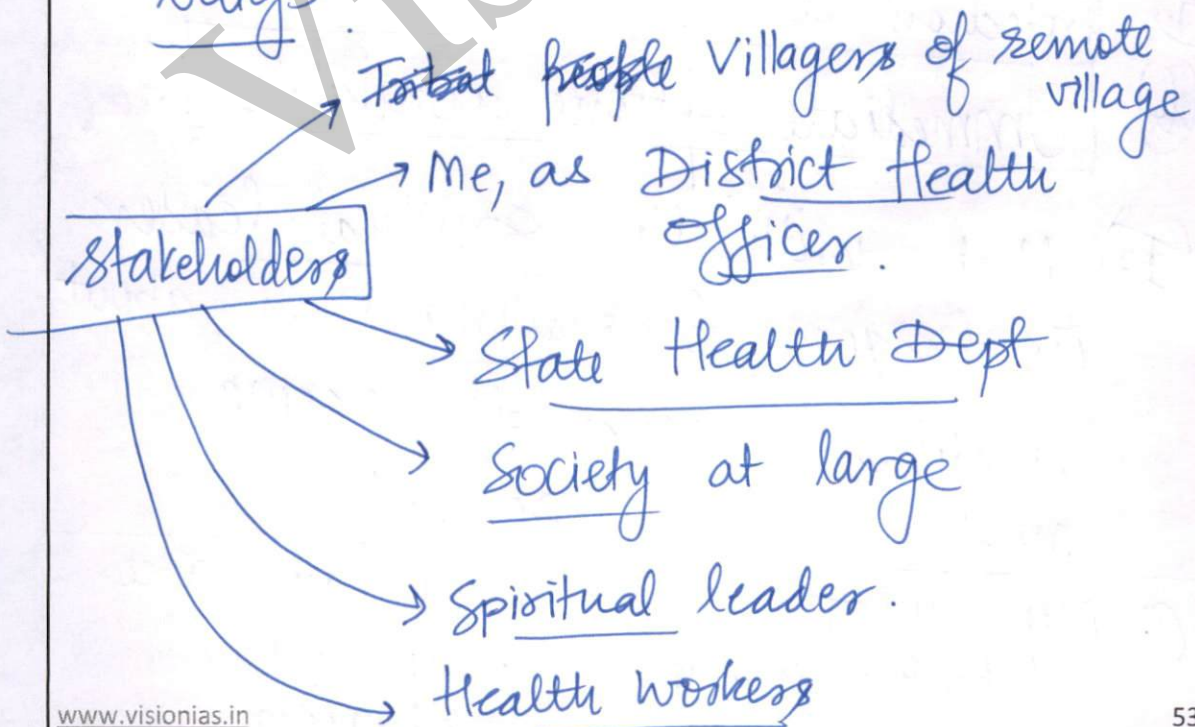
However, in one of the largest and most traditional villages in your district, you encounter formidable resistance. The villagers, deeply influenced by the pronouncements of a revered local

spiritual leader, firmly believe that vaccinations are an intrusion by malevolent spirits, an attempt by external forces to control their population, or will cause infertility in their children. They insist that their traditional herbal remedies and ritualistic blessings are sufficient protection. This spiritual leader, a genuinely well-meaning but unyielding figure, sincerely believes these vaccinations are harmful and has publicly advised his followers against them, citing anecdotal 'failures' and ancient prophecies. His word is paramount for the community's adherence to traditional ways of life. This has led to an almost complete boycott of the vaccination camps in the village, despite extensive awareness campaigns. Your health workers, some of whom are local and fear social ostracization or even physical harm, are facing intense hostility. The state health department is exerting immense pressure to achieve targets, warning of severe consequences for any district failing to meet the immunization goals. Simultaneously, they strictly caution against any use of force that could lead to public unrest, emphasizing the need for 'consensus-based' public health. An impending large annual fair, which will draw crowds from multiple villages and regions, heightens the immediate and severe risk of a rapid MR outbreak if this village remains unvaccinated, posing a grave threat to the wider district and potentially beyond.

- Discuss the ethical issues involved in the above case.
- What are the immediate options available to you to overcome this resistance?
- What long-term strategies and systemic reforms would you suggest to address the pervasive influence of superstition and foster a scientific temperament for sustainable public health outcomes? (Answer in 250 words)

20

This situation is similar to the vaccine hesitancy witnessed during COVID-19 in some tribal areas owing to traditional and superstitious beliefs.



(a) Ethical issues:

- ① Prevention of law and order situation
- ② Obligation to protect population against measles outbreak - as monsoon season and annual fair are imminent
- ③ Duty to be fulfilled as directed by state Health Department.
- ④ No use of force against individual consent.
- ⑤ Strong reverence of spiritual leader.
- ⑥ Respecting rights of people to deny vaccination
- ⑦ Protection of health workers

(b) Immediate options available:

(I) Meet with the spiritual leader in person persuading him about scientific evidence of vaccine

Merit ① My duty to public health service	Demerit ① May not agree with my opinion
---	--

① My reliance on
persuasive
skills

② Leader may
instigate his followers
to cause law & order
situation

Option 2: Addressing villagers to
persuade them by inviting doctors.

Merit

Demerit

① Evidence based
persuasion

① They only believe
in leader

② Credible source
highlighted

② may not budge.

Option 3: Seeking support of higher
authorities in deploying extra force in
district, persuading leader by warning
him about action on public health
endangerment, asking him to address
his followers

Merit

Demerit

① Addressing all
concerns

① may still not
agree

② My duty as officer
of courage

② villagers may
not consent

(1) Long-term strategies and systemic reforms

① Inclusion of scientific temperament in school curriculum

② Focus on evidence based learning at all levels of education

③ Strict action against such spiritual leaders who misguide public and threaten public health (Art 19(2))

④ Awareness creation by way of media and scientific programmes

⑤ Vigyan Wani on Doordarshan

The responsibility to protect public health is of ut most significance and public must be guided in their best interests

आप एक अत्यंत प्रेरित और सिद्धांतवादी प्रधान ग्राम पंचायत सचिव हैं। हाल ही में, आपको एक दूरस्थ जिले में स्थित एक बड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण गाँव में पदस्थ किया गया है। आपका तात्कालिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 'ग्रामीण आवास योजना' के लाभार्थियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना है — यह राज्य की एक प्रमुख आवासीय योजना है, जिसका उद्देश्य वास्तव में गरीब और भूमिहीन परिवारों को 'पक्का' (ईंटों से बना) घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की समय-सीमा बहुत कम है और निधियों की प्राप्ति सटीक व त्वरित लाभार्थी चयन पर निर्भर करती है। जिला कलेक्टर की ओर से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बल देते हुए किसी भी कदाचार के विरुद्ध स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गयी है।

वार्ड क्रमांक 3 में घर-घर जाकर मेहनत से किए गए आपके सत्यापन के दौरान, आपको पता चलता है कि श्री इंद्र सिंह, एक व्यापक रूप से स्वीकृत 'बाहुबली' व्यक्ति है, जिसके परिवार के पास अपनी भूमि और व्यापक स्थानीय नेटवर्क की वजह से महत्वपूर्ण अनौपचारिक शक्ति और प्रभाव है, को अस्थायी रूप से एक पात्र लाभार्थी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अवस्थिति पर आपके द्वारा किए गए आकलन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री सिंह एक विशाल, बहुमंजिला 'पक्के' घर में रहता है और उसकी वित्तीय स्थिति 'गरीबी रेखा से नीचे' जीवन-यापन करने वाले परिवारों हेतु योजना के सख्त पात्रता मानदंडों से काफी ऊपर है। जब आप उसकी पात्रता पर प्रश्न उठाते हैं, तो श्री सिंह अत्यधिक आक्रामक हो जाता है। वह अपने परिवार के गांव में 'अद्वितीय योगदान' और चल रहे उच्च प्राथमिकता वाले जिला स्तरीय 'जल सुरक्षा अभियान' के लिए समर्थन जुटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसका नाम हटाने की किसी भी कोशिश को न केवल एक गंभीर व्यक्तिगत अपमान माना जाएगा, बल्कि इससे उनके परिवार द्वारा जल अभियान से महत्वपूर्ण समर्थन भी वापस लिया जा सकता है, जिससे पूरे जिले के प्रयास खतरे में पड़ सकते हैं और इससे हजारों किसान प्रभावित होंगे। उसने आगे चेतावनी दी कि वह भविष्य में होने वाले विकास कार्यों के विरुद्ध व्यापक स्थानीय प्रतिरोध को उग्र कर सकता है, जिससे पंचायत का कामकाज पूरी तरह ठप्प हो जाएगा।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि कई वास्तविक रूप से ऐसे गरीब परिवारों हैं जो जीर्ण-शीर्ण झोपड़ियों में रहते हैं और दशकों से ऐसी सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं। श्री सिंह को शामिल करने से उनमें से किसी एक परिवार को अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर करना होगा। आपके खंड विकास अधिकारी (BDO), राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के भारी दबाव में, आपको व्यक्तिगत तौर पर 'विनम्र' होने और सभी सरकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'समग्र शांति और सहयोग' को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। उन्होंने यह संकेत दिया है कि श्री सिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों को चुनौती देने से आपके पूरे कार्यकाल में 'अनावश्यक बाधाएं' उत्पन्न हो सकती हैं और आपकी भावी नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ग्राम समुदाय, श्री सिंह के अनुचित दावे को जानकर भी, उनके विरुद्ध खुलकर बोलने से डरते हैं, जिससे उनकी अयोग्यता की बाह्य पुष्टि कठिन हो जाएगी और आप इस विषय पर अकेले पड़ जाएंगे।

- आपके समक्ष विद्यमान संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएं क्या हैं?
- आपके लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिए।
- आप अपने निर्णय का नैतिक औचित्य सिद्ध करते हुए कौन-सी व्यापक कार्यवाही करेंगे? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

You are a highly motivated and principle-driven Gram Panchayat Secretary, recently posted in a large and socio-economically diverse village in a remote district. Your immediate and most critical task is the meticulous verification of beneficiaries for the 'Gramin Awas Yojana' – a flagship state housing scheme aimed at providing 'pucca' (brick) houses to the genuinely impoverished and landless households. The scheme is under tight deadlines, with funds

dependent on swift and accurate beneficiary selection. The District Collector has explicitly warned against any malpractices, emphasizing fairness and transparency.

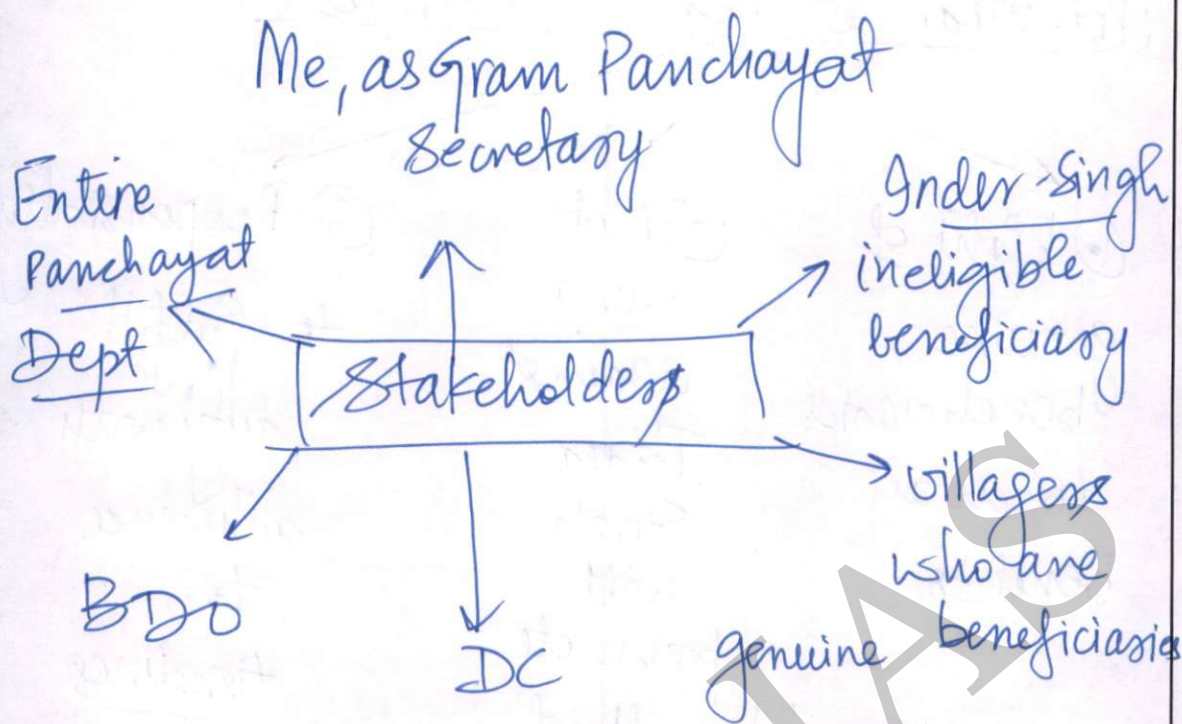
During your diligent house-to-house verification in Ward No. 3, you discover that Mr. Inder Singh, a widely acknowledged 'strongman' whose family wields significant informal power and influence due to their landholdings and extensive local network, has been provisionally listed as an eligible beneficiary. Your on-ground assessment unequivocally reveals that Mr. Singh resides in a sprawling, multi-story 'pucca' house and his financial status is demonstrably far above the scheme's strict eligibility criteria for 'Below Poverty Line' families. When you subtly question his eligibility, Mr. Singh becomes overtly aggressive, citing his family's 'unparalleled contribution' to the village and his crucial role in mobilizing support for the ongoing, high-priority district-level 'Jal Suraksha Abhiyan' (Water Conservation Campaign), where his active cooperation is currently indispensable. He bluntly states that any attempt to remove his name would not only be seen as a grave personal insult but could also result in his family's withdrawal of crucial support from the water campaign, potentially jeopardizing the entire district's efforts, which affects thousands of farmers. He further warns that he can incite widespread local resistance against future developmental works, effectively paralyzing the Panchayat's functioning.

You are keenly aware that several genuinely impoverished families, living in dilapidated shacks, have been waiting for decades for such assistance, and Mr. Singh's inclusion would directly mean one of them is unjustly excluded. Your Block Development Officer (BDO), under immense pressure to meet state targets, has privately advised you to be 'flexible' and prioritize 'overall peace and cooperation' to ensure the smooth rollout of all government schemes, hinting that challenging influential individuals like Mr. Singh might create 'unnecessary roadblocks' for your entire tenure and even impact your future postings. The village community, while silently aware of Mr. Singh's undue claim, fears openly speaking against him, making external validation of his ineligibility difficult and adding to your isolation.

- (a) What are the potential administrative and ethical dilemmas you face?
- (b) Discuss all options available to you.
- (c) What comprehensive course of action would you choose to adopt, providing ethical justification for your decision? (Answer in 250 words)

20

This case study is a case in point where exclusion and inclusion errors may lead to genuine beneficiaries facing inter-generational poverty.



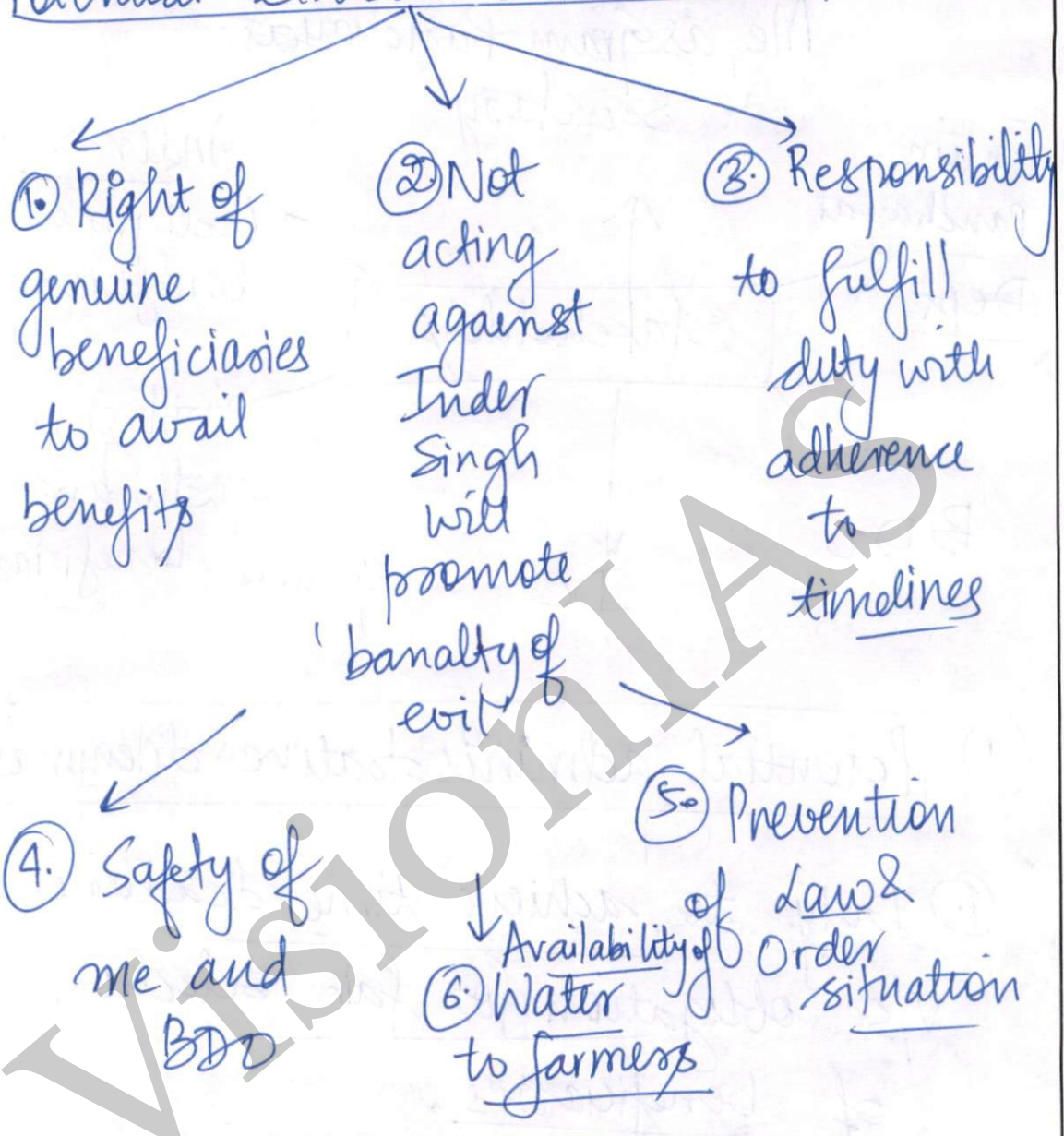
(a) Potential administrative dilemmas

① Duty to achieve time deadlines
v/s obligation for fair selection
of beneficiaries.

② Public interest in ongoing Jal
Suraksha Abhiyan v/s responsibility
for genuine housing beneficiaries

③ Silence of villagers against unjust
practice v/s their needs

Potential ethical dilemmas



(b) Options available :

Option : let Inder Singh be a beneficiary & submit the list

Merit	Demerit
1. Timeline adherence	1. <u>Cognitive crises</u>
2. No action against my private interest	2. Disreput of public trust.

option 2: Remove name of Inder Singh and submit correct name list

Merit	Demerit
① Adherence to principle of integrity	① May invite law & order situation
② No crises of conscience	② May be safety concern for myself & BDO

option 3: Inform the higher authorities about such inclusion, remove name, persuade villagers to speak against injustice and not to support Inder Singh

Merit	Demerit
① Upholding of transparency & accountability	① Villagers may be fearful.
② Promotion of public welfare	② Inder Singh may stop support for water scheme

(c) My course of action would be to choose option 3 :

- ① Informing higher authorities about misconduct will threaten Indar Singh against any unlawful action
- ② Obligation to act in public interest is upheld
- ③ My duty as a principle-driven Secretary is fulfilled.
- ④ No genuine beneficiary should be left behind- Antodaya
- ⑤ Promise of water to farmers as Indar Singh can't act now.

The acts in public service, no matter how grave the circumstances be, should be conducted with due diligence and transparency to prevent misuse of public money

SPACE FOR ROUGH WORK

~~VisionIAS~~

SPACE FOR ROUGH WORK

EAL

~~VisionIAS~~